Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2023 4(1), 4291–4295

CONTRIBUTION OF NGOS IN PROMOTING SPORTS

गैर सरकारी संगठनों का खेलों को बढ़ावा देने में योगदान

Mukesh Agarwal [1]

[1] Department of Physical Education, Maharaja Agrasen College, Delhi University, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i1.2023.5199

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

ABSTRACT

English: NGOs play an important role in increasing the scope of sports. They are actively involved in raising awareness about sports, building playgrounds, making arrangements for implementation of sports, training players, and organizing various arrangements to promote sports. NGOs work in collaboration with the government and other institutions in promoting sports, which means sports. Non-Government Organization, in Hindi we call it NGO. Well, it is a non-governmental organization but it works for the public in collaboration with the government. With the help of NGOs, all government schemes reach our doorstep. With the help of NGOs, the government does development work. These NGOs also work as an implementation agency.

Hindi: एनजीओ (NGOs) खेल को दायरे को बढ़ाना मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खेल के मैदानों का निर्माण करने, खेल के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था करने, खिलाड़ियों को अनुशिक्षण देने, और खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यवस्था आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। एनजीओ खेल को बढ़ावा देने में सरकार और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे खेल का अभिप्राय होता है।नॉन गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन (Non-Government Organisation), हिंदी में इसे हम गैर सरकारी संस्था कहते है। खैर गैर सरकारी संस्था हो लेकिन सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए काम करती है । एनजीओ की मदद से तमाम सरकारी योजनाएं हमारे दहलीज तक पहुंचती है। एनजीओ की मदद से सरकार विकास के काम करती है। ये एनजीओ कार्यान्वयन एजेंसी का भी काम करती है।

1. प्रस्तावना

एनजीओ (NGOs) खेल को दायरे को बढ़ाना मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने, खेल के मैदानों का निर्माण करने, खेल के लिए कार्यान्वयन की व्यवस्था करने, खिलाड़ियों को अनुशिक्षण देने, और खेल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न व्यवस्था आयोजित करने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। एनजीओ खेल को बढ़ावा देने में सरकार और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे खेल का अभिप्राय होता है।नॉन गवर्नमेंट आर्गेनाईजेशन (Non-Government Organisation), हिंदी में इसे हम गैर सरकारी संस्था कहते है। खैर गैर सरकारी संस्था हो लेकिन सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए काम करती है । एनजीओ की मदद से तमाम सरकारी योजनाएं हमारे दहलीज तक पहुंचती है। एनजीओ की मदद से सरकार विकास के काम करती है। ये एनजीओ कार्यान्वयन एजेंसी का भी काम करती है।

भारत में एनजीओ की संख्या 31 लाख है। देश में शिक्षालय की संख्या से दोगुना। सरकारी अस्पतालों की संख्या का 250 गुना। ये सच है, पूरे भारत में इतने NGO हैं कि हर 400 व्यक्ति पर एक NGO है। ज्यादातर NGO कागज़ों तक ही सीमित हैं। इसका मुख्य कारण है सही जानकारी का न होना, NGO में मैनेजमेंट का अभाव और सबसे महत्वपूर्ण धन का अभाव, इन एनजीओ के लिए वित्तपोषण का नहीं होना। वित्तपोषण प्रशासन नहीं होने से ज्यादातर NGO निष्क्रिय है। NGO को समाज सेवा या सामाजिक शुभद संबंधित कामों के लिए खोला जाता हैं लेकिन इससे समाज सेवा के साथ पैसा कमाने, टैक्स बचाने, राजनीति में करियर बनाने जैसे बहुत से व्यक्तिगत लाभ को अगर कोई देखता है तो वही एनजीओ की अहमियत खत्म हो जाती हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के गठन से आप प्रॉफिट (Profit) कमाने की सोच नहीं रख सकते। सामान्य रूप से यह नॉन प्रॉफिट के सिद्धांत का अनुपालन करता है।

एनजीओ कई तरीकों से फंडिंग जुटा सकते हैं, सरकारी व प्राइवेट कंपनियां एनजीओ को ग्रांट दे सकती हैं, यहां तक कि पीएसयू और कॉर्पोरेट्स अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल एनजीओ के जरिये करवा सकती है। ये पीएसयू और कॉर्पोरेट्स NGO को एम्प्लिमेंटिंग एजेंसीज के तौर पर नियुक्त भी कर सकती हैं। तमाम बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के सीएसआर (CSR Funds) फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड गरीबों, ज़रूरतमंदों तक एनजीओ के माध्यम से ही पहुंचते हैं। इसी प्रकार से कई सारे एनजीओ सामाजिक चिंताओं और कुरीतियों को दूर करने के लिए ही कार्य करते हैं। एनजीओ के काम समाज कल्याण से जुड़े हुए होते हैं।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) नियमों के तहत सामाजिक काम करने के लिए सीएसआर कानून के समय सारिणी में कुछ काम निर्धारित है। जितने भी एनजीओ है। वो सभी काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गरीब लोगों तक संपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जीविका वृद्धि संबंधी परियोजनाओं, स्वच्छता को बढ़ावा देना है। भारत सरकार भी संपूर्ण परियोजनाएं चलती है, स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना जैसी योजनाएं भारत सरकार चलाती है। इनका इम्प्लीमेंटेशन यही एनजीओ करती है। जिसके लिए इन NGO को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय ग्रांट यानी फंडिंग देते हैं। मंत्रालय वर्तमान में लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, वृद्धों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन, दिव्यांग के कल्याण के लिए विशेष रूप पृथक डिज़ाइन की गई स्कीमों के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्गों गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है।

2. भारत में खेल की भागीदारी

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि खेल युवाओं में व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल के विकास के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। खेल को पेशा के रूप में देखे जाने की संभावना अन्य पारंपरिक करियर विकल्पों की तुलना में इसकी स्थिति एवं वरीयता के प्रश्न को जन्म देती है।

- भारत में खेलों को करियर के रूप में अपनाने की राह में सामाजिक-आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, आहार संबंधी आदतें, सामाजिक वर्जनाएँ और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी कई बाधाएँ शामिल हैं, जो भारत की युवा महत्वाकांक्षी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को खेल के प्रति अपने उत्साह को बनाए रखने से हतोत्साहित करती हैं।
- भारत में खेल प्रशासन (Sports Governance in India) को नया रूप देने और खेल संस्कृति के लोकतंत्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

3. भारत में खेल शासन का इतिहास

- 1950 के दशक की शुरुआत में केंद्र सरकार ने देश में खेलों के गिरते मानकों को समझने के लिये अखिल भारतीय खेल परिषद (All India Council of Sports- AICS) का गठन किया।
- वर्ष 1982 में एशियाई खेलों (Asian games) के आयोजन बाद खेल विभाग (Department of Sports) को युवा कार्यक्रम और खेल विभाग (Department of Youth Affairs and Sports) में रूपांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy) का निर्माण हुआ।
- वर्ष 2000 में विभाग को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports- MYAS) में रूपांतरित कर दिया गया।
- वर्ष 2011 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (National Sports Development Code of India 2011) को अधिसूचित किया।
- वर्ष 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एरोबेटिक्स, एरो-मॉडलिंग, बैलूनिंग, ड्रोन, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग आदि के लिये राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 (NASP 2022) शुभारंभ की गई।

खेल क्षेत्र से संबंधित सरकार की विभिन्न पहलें

फिट इंडिया मूवमेंट

खेलो इंडिया

SAI प्रशिक्षण केंद्र योजना

खेल प्रतिभा खोज पोर्टल

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

4. भारत में खेल क्षेत्र से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ

- क्रीड़ा के प्रति पारिवारिक रुझान की कमी: भारत में अधिकांश परिवार अपने बच्चों पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और इंजीनियर, डॉक्टर या सफल उद्यमी बनने के लिये कड़ी मेहनत करने का बोझ रखते हैं।

इसमें अंतर्निहित भावना यह है कि खेलों में योग्य आजीविका पल का अभाव है और ये एक समृद्ध जीवन के संचालन में सहारा नहीं कर सकते।

- सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ: सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का भारतीय खेलों पर नकारात्मक असर रहा है।

गरीबी के कारण आधारभूत खेल अवसंरचना तक पहुँच की कमी, स्टेडियमों तथा अन्य खेल अवसंरचनाओं एवं अवसरों का महानगर में केंद्रित होना, बालिकाओं के लिये खेलों में भाग लेने हेतु समर्थन की कमी आदि ने देश में एक सकारात्मक खेल रीति-रिवाज के विकास को बाधित किया है।

- नीतिगत कमियाँ: किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये एक प्रभावी नीति का निर्माण और क्रियान्वयन एक शर्त है।

खेलों के संवाद में भी यही बात लागू होती है। अभी तक की स्थिति यह है कि संसाधनों अभाव के कारण देश में खेल नीति नियोजन एवं कार्यान्वयन केंद्रीकृत है, जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, ओलंपिक खेलों में बिडिंग स्कैम, महिला हॉकी टीम में यौन उत्पीड़न जैसी कई घटनाओं का कारण बना है।

- भ्रष्टाचार और खेल प्राधिकरणों का कुप्रबंधन: भारत में खेल प्रशासन भ्रष्टाचार का पर्याय ही बन गया है।

चाहे वह सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट हो या हॉकी अथवा भारोत्तोलन, भारत में अधिकांश खेल प्राधिकरण भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निशाने पर हैं।

इसके अलावा, लंबे समय तह खेल निकायों के प्रबंधन से राजनीतिक मनुष्य की संलग्नता और 'राष्ट्रमंडल खेल 2010' से जुड़े विवादों ने भारत में खेल प्रशासकों की छवि को मलिन किया।

- प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग: इस क्षेत्र में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं (Performance Enhancing Drugs) का उपयोग अभी भी एक बड़ी समस्या है। एंटी-डोपिंग नियम के उल्लंघनों (Anti-Doping Rule Violations) या वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्षों (Adverse Analytical Findings) में भारत पहले स्थान पर रहा है।

देश में एंटी-डोपिंग संस्था के गठन के बावजूद अभी भी इस समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना शेष है।

- खेल के खाली मैदान: प्रौद्यिगिकी और वीडियो गेम्स ने बच्चों को शारीरिक खेल में संलग्न होने से दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। खेल के मैदान में मित्रों के साथ खेलने के बजाय सचल दूरभाष यंत्र पर अधिक व्यस्त रहते हैं। इसके कारण छोटे बच्चे कम उम्र में ही मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

5. NGOS की अहम भूमिकाएं

- खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना:

NGOs खेल के महत्व और इसके लाभों के बारे में प्रजा के बीच जागरूकता फैलाते हैं, जिससे अधिक लोग खेल में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं।

- खेल के मैदानों का निर्माण करना:

NGOs खेल के मैदानों और अन्य सुविधाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो खेल के विकास के लिए आवश्यक हैं।

- खेल के लिए उपकरणों की व्यवस्था :

NGOs खेल के लिए उपकरणों और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करते हैं, जो खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने में मदद करते हैं।

- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना:

NGOs खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

- खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम व्यवस्थापित करना:

NGOs खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम व्यवस्थापित करते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट, शिविर, और खेल प्रतियोगिताओं, जिससे खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है।

- युवाओं का विकास:

NGOs युवा खिलाड़ियों को समर्थन प्रदान करते हैं और उनके विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे वे बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं और नागरिक बन सकते हैं।

- सामाजिक समावेशिता:

NGOs खेल को बढ़ावा देने के लिए समूहों को भी शामिल करते हैं, जिससे सभी को खेल का आनंद लेने का अवसर मिलता है और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। इन एनजीओ के साथ मिलकर वॉलेंटियर्स बनकर बेहद ही सराहनीय काम करते है।

- स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा

NGOs खेल में बढ़ावा देकर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

6. भविष्य की राह

खेल संस्कृति का लोकतंत्रीकरण: खेल में शासन के लिये एक सुदृढ़ ढाँचे का निर्माण कर भारत की खेल संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर पुनर्जीवित की आवश्यकता है।

1. भारतीय शिक्षा प्रणाली में खेलों को भूतकालिक रूप से पीछे छोड़ दिया गया है। खेलों के प्रति विद्यालयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन में भारत में खेल परिदृश्य को नया रूप देने की क्षमता है।

2. फिट इंडिया मूवमेंट' में कहा गया है कि विद्यालय अपने पाठ्यक्रम में पारंपरिक और क्षेत्रीय खेलों को शामिल कर सकते हैं लेकिन खेल को पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य घटक बनाने को अभी और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

सभी खेलों के लिये समान प्रोत्साहन: यह प्रासंगिक समय है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र भारतीय खेल क्षेत्र को वर्तमान दुर्गम स्थिति से उबारने के लिये साथ आएँ।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: उन प्रथा को तोड़ने की आवश्यकता है जो महिलाओं के खेल गतिविधियों में शामिल होने की संभावना को कम करती हैं। इसका अर्थ खेल क्षेत्र में पेशेवर एथलीटों और नेतृत्वकर्ताओं के रूप में महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा देना भी है। इसके साथ ही, महिला खेल में निवेश के अंतर को भरने और महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। BCCI द्वारा हाल ही में क्रिकेट में लैंगिक वेतन समानता (Gender Pay Parity) लागू करना इस दिशा में उत्साहवर्धक कदम है।

7. अवसंरचनागत कमियों दूर करना

खेल अवसंरचना में निवेश: स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र, अभ्यास सुविधाएँ, जिम और पुनर्वास केंद्र जैसे आधारभूत ढाँचों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तुल्य जाना चाहिये। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी इन सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है प्रतिभाएँ केवल शहर तक सीमित न रहें।

खेल उपचार और विज्ञान: प्रदर्शन में सुधार लाने और खिलाड़ियों की चोटों से उबरने की प्रक्रिया को कुशल बनाने हेतु खेल उपचार, पोषण, फिजियोथेरेपी और मनोचिकित्सक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए।

अनुसंधान एवं विश्लेषण: क्रीड़ा डेटा विश्लेषण, प्रदर्शन मूल्यांकन और तकनीकी सुधार हेतु विशिष्ट अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि प्रशिक्षक और खिलाड़ी अपने खेल को बेहतर बना सकें।

क्षेत्रीय खेल केंद्र: देशभर में क्षेत्रीय खेल केंद्रों की स्थापना से स्थानीय हुनर को प्रशिक्षित करने, उनकी पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह प्रतिभा पलायन को रोक सकता है।

आजीविका अवसरों का महासागर: सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी (SAOT)एक AI सेंसर जिसका उपयोग फीफा विश्व कप 2022 में ऑफसाइड का पता लगाने के लिये किया जा रहा है। निपुण हस्तक्षेपों से खेलों में क्रांति आ रही है।

क्रीड़ा में इस तकनीकी क्रांति के माध्यम से नए रोज़गार अवसर हो रहे हैं, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के क्षेत्र में। इससे भारत के युवा जनसांख्यिकीय लाभांश को फायदा पहुँच सकता है।

8. निष्कर्ष

NGOs खेल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे क्रीड़ा के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं. उनके प्रयासों से क्रीड़ा का विकास होता है और समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।